सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 1- सहभागी सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता

विषय 1.2 पारंपरिक नहर सिंचाई प्रबंधन की समस्याएँ

विषय-1.2

पारंपरिक नहर सिंचाई प्रबंधन की समस्याएँ

मॉड्यूल-1 के विषय

1.1 देश में कृषि तथा सिंचाई की स्थिति
1.2 पारंपरिक नहर सिंचाई प्रबंधन की समस्याएँ
1.3 सहभागी सिंचाई प्रबंधन की अवधारणा तथा आवश्यकता
1.4 सहभागी सिंचाई प्रबंधन के सफल उदाहरण

पारम्परिक नहर सिंचाई प्रबंधन की समस्या

यद्यपि नहरें सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन हैं, परन्तु निम्नलिखित कारणों से नहर सिंचाई प्रबंधन उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है-

- विभाग द्वारा नहर की मरम्मत, गाद और सफाई समय से न हो पाने के कारण नहर में उसकी पूरी क्षमता से पानी नहीं जा पाता है।

- नहर में कब, कितने समय के लिए और कितना पानी आयेगा, इसकी पर्याप्त जानकारी प्रायः किसानों को नहीं रहती। इससे वे फसल लगाने और सिंचाई करने की अग्रिम योजना नहीं बना पाते।
- अग्र भाग के किसानों के ज्यादा पानी ले लेने के कारण नहर के अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है और उस हिस्से के खेत सूखे रह जाते हैं। इस हिस्से के किसानों को सिंचाई के लिये अन्य स्रोतों जैसे नलकूप इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनका खेती का खर्च बढ़ जाता है और आय कम हो जाती है।
- नहर से जल प्राप्त न होने के कारण कमाण्ड क्षेत्र के अंतिम छोर के क्षेत्रों में भू-गर्भ जल का जम कर दोहन होता है।
- अपनी बारी आने का भरोसा न होने के चलते जिसे मौका मिलता है, विशेष कर नहर के अग्र भाग के किसान, जरुरत से ज्यादा पानी ले लेते हैं। इससे विवाद पैदा होते हैं, साथ ही बहुमूल्य कृषि योग्य भूमि भी खराब होती है।
- सिंचाई के पानी का संतोषजनक और उचित उपयोग न हो पाने के कारण किसान सिंचाई कर भी नहीं देना चाहते। परिणामस्वरुप सरकार को सिंचाई कर की पूरी प्राप्ति नहीं हो पाती और परियोजना घाटे में रहती है। इसका सीधा असर बाद में सिंचाई प्रणालियों की मरम्मत व रखरखाव पर पड़ता है।
- सिंचाई राजस्व में घाटा होने से सिंचाई विभाग के पास मरम्मत इत्यादि कार्यो के लिए हमेशा धन की कमी रहती है।
- सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव में किसानों की भागीदारी का अभाव बड़ी समस्या है।
- सिंचाई विभाग के पास कुशल कर्मियों की कमी है और समय से धन का आवंटन न हो पाने की भी समस्या बनी रहती है। दूसरी ओर किसान समय से सिंचाई न होने के चलते उत्पादन और फलस्वरुप आय में कमी की समस्या से त्रस्त रहते हैं।

- कुछ किसान इस अव्यवस्था को दूर करने में योगदान करना चाहते हैं, परन्तु संगठन के अभाव में उन्हें अन्य किसानों का सहयोग नहीं मिलता।

वर्तमान सिंचाई व्यवस्थाओं से किसान स्वयं को दुष्चक्र में फंसा महसूस करता है जैसा नीचे दिखाये गये चार्ट में दर्शाया गया है-

चित्र-1: वर्तमान सिंचाई व्यवस्थाओं का दुष्चक्र

जैसा कि ऊपर के दुष्चक्र में दिखाया गया है, विभाग एवं किसानों के मध्य संवादहीनता गंभीर समस्या है। इस कारण नहरों में जल की उपलब्धता की सटीक जानकारी हमेशा ढुलमुल बनी रहती है। इसके चलते नहरों में पानी छोड़े जाने के समय किसान अधिक से अधिक पानी एक बार में ही ले लेना चाहते हैं। नहर के अग्र भाग के किसानों द्वारा असमानुपातिक जल लेने के कारण पीछे के किसानों के पास पानी समय से नहीं पहुंच पाता। इससे उनके उत्पादन में कमी आती है और परिणामस्वरुप राजस्व में भी कमी आती है। कृषकों का नहर से लगाव कम होता जाता है। नहर मरम्मत हेतु पर्याप्त धन की कमी तथा सरकारी तंत्र पर सिंचाई प्रबंधन के अतिरिक्त अन्य कार्यों का बोझ, अवांछित दबाव के

अलावा कृषकों एवं सिंचाई विभाग के मध्य संवादहीनता के कारण नहर की मरम्मत उचित प्रकार से एवं समय से नहीं हो पाती है। इसका सीधा प्रभाव नहर जल के समुचित प्रबंधन पर पड़ता है।

इसे समझने कि लिये आप अन्य साथियों की सहायता से अपने गांव की नहर सिंचाई का अध्यन करें तो इस विषय में अधिक समझ बढेगी।

व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता

सिंचाई से जुडे पक्षो का सुस्त और हठी रवैया अपने आप में बड़ी समस्या है। पारम्परिक नहर सिंचाई प्रबंधन में दो पक्ष हैं- एक सिंचाई विभाग व दूसरा किसान। विभाग की सोच है कि वह सिंचाई प्रणालियों का मालिक है और उन्हें किसानों को सिंचाई की सुविधा देनी है, परन्तु किसान सहयोग नहीं करते है | दूसरी ओर किसान समझते है कि नहरें तो सरकार ने बनवाई है और इनके रखरखाव व जल वितरण की जिम्मेदारी केवल सिंचाई विभाग की है, और उन्हें तो बस पानी से मतलब है। लम्बे समय से विभाग और किसान दोनों अपनी इस सोच पर कायम हैं, परन्तु अब समय आ गया है कि दोनों पक्ष मिलजुल कर साझीदार संस्थाओं के रुप में कार्य करें। पुरानी कहावत है कि ताली दो हाथों से ही बजती है।

बदलते परिवेश में जहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी समस्या से परेशान हैं, क्या ये हो सकता है कि दोनों पक्ष मिल कर इस समस्या को दूर करें ? क्या ऐसा हो सकता है कि किसान अपने संगठन के माध्यम से और विभाग के सहयोग से नहरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले और सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव, मरम्मत, जल वितरण और सिंचाई से जुड़ी तमाम चीजों की जिम्मेदारी स्वयं उठायें ?

नुकसान की कीमत कौन चुका रहा है ..?

डेवलपमेन्ट सपोर्ट सेन्टर, अहमदाबाद द्वारा किये गये एक अनुसंधान के अनुसार सहीं समय पर सिंचाई न होने के कारण नहर कमाण्ड में गेहूँ उगाने वाला एक किसान प्रति वर्ष लगभग 10000 रुपये वार्षिक नुकसान उठाता है। सौ किसानों पर नुकसान का यह आंकड़ा दस लाख रुपये होता है। तो वे क्या करें ? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें या मिलजुल कर नहर की व्यवस्था अपने हाथों में ले लें ? आखिर नहरों की सफाई व छोटी-मोटी मरम्मत का खर्च हर साल होने वाले 10 लाख रुपये के नुकसान से तो कम ही होगा, तो अब और इंतजार नहीं। आइये, मिलजुल कर कुछ करें... किसान सिंचाई व्यवस्था अपने हाथ में लें और अधिकारी उन्हें मार्गदर्शन व सहयोग दें। बदलाव का यही रास्ता है। जिसमे लागत कम और मुनाफा ज्यादा है|